ISSN 2278 - 0327

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यकता एवं उपयोगिकता का अध्ययन

डॉ. मोहन लाल 'आर्य'
प्रोफेसर, शिक्षा विभाग
आईएफटीएम विश्वविद्यालय, मुरादाबाद, उ.प्र.

सार:- *शिक्षा किसी भी राष्ट्र में प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है और शिक्षा ही एक ऐसी बुनियाद है, जिससे व्यक्ति, समाज तथा देश की तरक्की एवं समृद्धि सुनिश्चित होती है। शिक्षा एक ऐसा साधन है जो किसी भी देश के बच्चों से लेकर युवाओं तक के भविष्य का निर्माण करती है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि देश के विकास को गति देने वाली शिक्षा व्यवस्था भी गतिक हो जिससे बदलते समाज एवं समय के साथ बच्चे आधुनिकतम् तौर-तरीकों से परिचित हो सकें। इसलिए मेरे विचारों से शिक्षा का बहु प्रतीक्षित स्वदेशीकरण तथा नई तकनीकियों के साथ ताल-मेल बैठाकर सतत् विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु भारत में नई शिक्षा नीति की आवश्यकता एक लम्बे समय से महसूस की जा रही थी, चूँकि शिक्षा नीति किसी भी राष्ट्र की मूलभूत आवश्यकता होती है, जिसमें अतीत का विश्लेषण, वर्तमान की आवश्यकता तथा भविष्य की सम्भावनाएँ निहित होती हैं। इसी आवश्यकता को देखते हुए हमारे देश की केन्द्र सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य छात्रों की सोच और रचनात्मक क्षमता को बढ़ाकर सीखने की प्रक्रिया को और अधिक कुशल एवं प्रभावी बनाना तथा स्कूल एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव लाना रखा गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को शिक्षा के क्षेत्र में सावधानीपूर्वक क्रियान्वित कराये जाने की बहुत ही अवश्यकता है, जिससे आने वाले दशकों में भारतीय शैक्षिक संरचना में सार्थक बदलाव सम्भव हो सके तभी इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 की सार्थकता सिद्ध हो सकती है।*

मुख्य शब्द:- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, रचनात्मकता, शिक्षा, उद्देश्य, विकास, लक्ष्य।

प्रस्तावना-

शिक्षा के इतिहास में आदिकाल से विविध प्रकार से विकास एवं प्रसार होता रहा है। शिक्षा के माध्यम से ही प्रत्येक देश अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिति को अभिव्यक्ति देने एव उसे समृद्ध बनाने, नवीन चुनौतियों का सामना करने के लिये समयानुसार विशिष्ट प्रणाली विकसित करता है। प्राचीन भारत में जिस शिक्षा व्यवस्था की संरचना की गई थी, वह समकालीन वैश्विक शिक्षा व्यवस्था से विकसित व उत्कृष्ट थी, परन्तु कालांतर में भारत की शिक्षा व्यवस्था का पतन होता गया, क्योंकि विदेशियों ने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को जिस अनुरूप होना चाहिए, उस तरह से विकसित नहीं किया। संक्रमण काल खण्ड में भारतीय शिक्षा को अनेक चुनौतियों एवं समस्याओं का सामना करना पड़ा। सन् 1850 तक भारत में गुरूकुल शिक्षा व्यवस्था चलती रही। कालान्तर में मैकाले द्वारा अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के संक्रमण के कारण भारत की प्राचीन एवं पारम्परिक शिक्षा व्यवस्था का अंत हो गया और भारत में संचालित कई गुरुकुल शिक्षा केन्द्र बन्द हो गए और उनके स्थान पर कान्वेन्ट तथा पब्लिक स्कूल शिक्षा व्यवस्था पर जोर दिया जाने लगा। ब्रिटिश काल में शिक्षा के क्षेत्र में मिशनरियों का प्रवेश हुआ तथा इस काल में 'मैकाले का घोषणा-पत्र 1835', वुड का घोषणा-पत्र 1854 तथा 'हण्टर आयोग 1882' पारित किए गए। मैकाले की शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य था कि संस्कृत, फारसी तथा लोक भाषाओं के वर्चस्व को समाप्त करके अंग्रेजी शिक्षा का वर्चस्व कायम किया जाए जिसमें ईसाई मिशनरियों को महत्वपूर्ण भूमिका दी गयी, परन्तु मार्च- 1890 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सम्बंधी प्रस्ताव दिया गया। 1929 ई0 में हर्टांग समिति ने प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि नहीं, बल्कि गुणवत्तापरक उन्नति पर जोर दिया। तत्पश्चात् गांधी जी द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षा का लक्ष्य बालकों का सर्वांगीण विकास करके उसे आत्मनिर्भर आदर्श नागरिक बनाने का प्रस्ताव सुझाया गया।

स्वतंत्रता के पश्चात् 1948-1949 में राधाकृष्ण आयोग, 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग (मुदालियर आयोग), 1964 में कोठारी आयोग तथा 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (प्रथम) आदि सुझावों के द्वारा भारतीय शिक्षा व्यवस्था को समय-समय पर सही दिशा-निर्देश देने की कोशिश की गयी। सन् 1986 में द्वितीय नई राष्ट्रीय शिक्षा-नीति लागू की गई, जिसमें शिक्षा के विकास के लिए व्यापक ढॉचा, आधुनिकीकरण तथा बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने पर जोर देने की बात कही गयी थी, जिन्हें पूरा करने में नई शिक्षा नीति 1986 पूर्णतः सफल नहीं रही। शिक्षा से सम्बन्धित घोषणाएँ, घटनाएँ, आयोग एवं नीतियों की सबसे बड़ी विडम्बना यह रही कि प्रथम शिक्षा नीति 1968 एवं द्वितीय नई शिक्षा नीति 1986 के बावजूद भी सरकारों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अमूल-

चूल परिवर्तन नहीं किया जा सका, जिससे विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों की ढांचागत एवं अध्ययन-अध्यापन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को आज भी देखा जा सकता है। इन्हीं शैक्षणिक कमियों एवं समस्याओं को देखते हुए एक नई शिक्षा नीति की आवश्यकता महसूस हुई। इसी को देखते हुए जून-2017 में 'इसरो' के पूर्व प्रमुख डॉ. के. कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप प्रस्तुत किया, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्री 'डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने 29 जुलाई 2020 को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की सहमति के उपरान्त मंजूरी प्रदान की जिसे 'नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 नाम दिया गया।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020- केन्द्र सरकार ने 'नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' को 29 जुलाई 2020 को मंजूरी प्रदान की। यह शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी। इसे 21 वीं सदी की पहली शिक्षा नीति भी कहा गया। इस शिक्षा नीति के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में देश की कुल जीडीपी के 6 प्रतिशत के हिस्से के बराबर निवेश का भी लक्ष्य रखा गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है-

अध्यक्ष-डॉ. के कस्तूरी रंगन (वैज्ञानिक व पूर्व इसरो प्रमुख एवं पद्म विभूषण)

समिति का नाम- कस्तूरी रंगन समिति।

समिति का गठन- इस समिति का गठन जून 2017 में किया गया तथा मई-2019 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया।

समिति को मंजूरी- इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को केन्द्रीय मंत्रीमण्डल द्वारा मंजूर कर लिया गया।

इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। हालाँकि 1985 से पहले यह मंत्रलाय 'शिक्षा मंत्रालय' ही था, जिसे 1985 में बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने के लिए लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें, 6600 ब्लॉक और 650 जिलों से राय एवं विचार लिए गए जिसमें शिक्षाविदों, अध्यापकों, अभिभावकों तथा व्यापक स्तर पर छात्रों से भी सुझाव लेकर उस पर गहन मंथन किया गया। तत्पश्चात् जन आकांक्षाओं के अनुरूप राष्ट्रीय आवश्यकताओं एवं चुनौतियों के मद्देनजर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि ''यह शिक्षा के क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित सुधार है, जिससे लाखों लोगों का जीवन बदल जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत इसमें संस्कृत समेत विभिन्न भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।'' इस नई शिक्षा नीति का लागू होना शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक, साहसिक एवं दूरगामी दृष्टिकोण वाला कार्य है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्य एवं लक्ष्य-

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 द्वारा भारतीय शिक्षण व्यवस्था में अमूल-चूल परिवर्तन हेतु निम्नलिखित उद्देश्य रखे गए-

1. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 क्या सोचना है के स्थान पर कैसे सोचना है पर केन्द्रित है।
2. इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संस्कृत एवं हिन्दी के साथ-साथ कई अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के प्रसार एवं विकास का लक्ष्य एवं उद्देश्य रखा गया है।
3. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 में कौशल विकास पर विशेष जोर देने की बात की गयी है।
4. इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेल-कूद, शारीरिक शिक्षा तथा योग शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ने का उद्देश्य रखा गया है।
5. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में विषयों की सीमा को खत्म करके शिक्षा को और आसान बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
6. इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दसवीं एवं बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं में कई अहम् बदलाव करके परीक्षाओं को आसान बनाने की पूरी कोशिश की गयी है।
7. इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्नातक स्तर पर शिक्षा को आसान एवं सरल करने हेतु प्रथम वर्ष पूरा करने पर प्रमाण-पत्र, द्वितीय वर्ष पूरा करने पर डिप्लोमा तथा अंतिम वर्ष पूरा करने पर डिग्री प्रदान करने का उद्देश्य रखा गया है।
8. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 का सबसे प्रमुख उद्देश्य 'ऑन लाइन शिक्षा' को बढ़ावा देने को रखा गया है, जिसमें ऐप्स, टी0वी0 चैनल एवं अन्य तकनीकि माध्यम से शिक्षा देने की बात की गयी है।
9. इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुल जीडीपी का लगभग 6 प्रतिशत भाग खर्च करने का भी लक्ष्य रखा गया है।
10. इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नई शिक्षण व्यवस्था 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 के सिद्धान्त पर काम करने का लक्ष्य रखा गया है।
11. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 का सबसे प्रमुख उद्देश्य यह है कि वर्ष 2030 तक के लिए वैश्विक सतत् विकास लक्ष्य-4 (एसडीजी-4) के अन्तर्गत गुणवत्तापरक शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 में सकल नामांकन को 26.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थाओं में 3.5 करोड़ नई सीटों को बढ़ाने का भी लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त कॉमन एडमिशन टेस्ट, अंतर्राष्ट्रीयकरण, शिक्षकों से सम्बन्धित सुधार, ई-पाठ्यक्रम एवं राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन को भी पूर्णतः विकसित करने का लक्ष्य रखा गया।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 की उपयोगिकता एवं सुझाव-

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को प्रस्तुत करते हुए शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने कहा कि ''देश के प्रधानमंत्री ने एक

नए भारत के निर्माण की बात की है जो स्वच्छ भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा, सशक्त भारत होगा, समृद्ध भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा। उस नए भारत के निर्माण में यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 मील का पत्थर साबित होगी।'' नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 की संकल्पनाओं का उद्घाटन करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि ''यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ज्ञान-विज्ञान, अनुसंधान नवाचार, प्रौद्योगिकी एवं मूल्य परक हरक्षेत्र में हर परिस्थितियों का मुकाबला करने वाली पूरी दुनिया के लिए भारत की महाशक्ति के रूप में उभर कर आएगी।'' नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लागू होना शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक, साहसिक एवं दूरदर्शी दृष्टिकोण वाला कार्य है, जिसके लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा रोड मैप भी तैयार किया गया है और इस नीति के सभी प्रावधानों को लागू करने की एक समय सीमा भी तय की गयी है। लगभग 75 प्रतिशत प्रावधानों को 2024 तक लागू करने का लक्ष्य भी है। शेष प्रावधानों को भी 2035 तक चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी, जो केन्द्र एवं राज्यों के बीच शिक्षा नीति के अमल पर हर वर्ष समीक्षा करेगी। यदि इस शिक्षा नीति को भारत सरकार द्वारा नियत समय सीमा के अंतर्गत लागू किया गया तो मुझे पूरा विश्वास है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में अमूल-चूल परिवर्तन हो कर ही रहेगा। तभी इस शिक्षा नीति की सार्थकता भी सिद्ध हो सकेगी। नीतियों का बनाना बड़ी बात नहीं होती है, बल्कि उसे धरातल पर उतारना जन-जन तक पहुंचाना तथा पूर्णतः लागू कराना चुनौती बनी रहती है। ऐसे में कौशल के आधार पर आत्म-निर्भर भारत का संकल्प रखने वाले भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का संकल्प यह नई शिक्षा नीति पूर्णतः लागू होने पर ही पूरी हो सकेगी। ऐसे में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 प्रभावी होकर एक नए भारत की नींव रख सकेगी और इसकी सार्थकता भी सिद्ध हो सकेगी।

निष्कर्ष:-

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि सैद्धान्तिक रूप से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत भारत की पुरातन व महान ज्ञान परम्पराओं तथा चिर-अर्जित वैज्ञानिक एवं बौद्धिक सम्पदाओं की संचित करने का प्रयास किया गया है। है। इसमें आधुनिक ज्ञान-विज्ञान तथा तकनीक के साथ नवीन उपलब्धियों के अपूर्व समन्वय की संकल्पना की गई है। शिक्षा की रंटत पद्धति के स्थान पर आलोचनात्मक, क्रियात्मक एवं मूलचिंतन तथा वैज्ञानिक सोच को प्रथमिकता दी गई है। शिक्षा माफिया के गढ़ो को ध्वस्त करने, अभिजात्यवाद के प्रचलन पर अंकुश लगाने और प्रारम्भिक चरण से ही कौशल विकास का मार्ग खोलने के लिये प्रतिबद्ध होने का प्रयास किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में जिन दो प्रमुख संस्थानों के गठन का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, वह एक निहायत सुविचारित परिकल्पना पर आधारित है परन्तु उपरोक्त वर्णित चुनौतियों व सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का व्यावहारिक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित लग रहा है।

संदर्भ ग्रन्थ-

- ''नई शिक्षा नीति पर बीजेपी अध्यक्ष जे.पी.नड्डा बोले- नई शिक्षा नीति नए भारत की जरूरतों को ध्यान में रखती है'' पंजाब केसरी 29 जुलाई 2020 अभिगमन तिथी 30 जुलाई 2020।
- 'नई शिक्षा नीति 2020: प्रमुख पाइन्ट्स एक नजर मे' 30 जुलाई 2020 अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020।
- 'नई शिक्षा नीति 2020' अमर उजाला अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020।
- 'नई शिक्षा नीति' नव भारत टाइम्स अभिगमन तिथि 31 जुलाई 2020।
- सिंह, प्रोफेसर दिनेश (29 जुलाई 2020) स्कूली और उच्च शिक्षा की बेडियां खोलेगी नई शिक्षा नीति अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020।
- ''नई शिक्षा नीति कितनी बदलेगी शिक्षा व्यवस्था'' आज तक, अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020।
- 'आर्य', डॉ0 मोहन लाल (2023) 'नई शिक्षा नीति 2020: एक शैक्षिक अध्ययन', Jyotirveda Prasthanam, 12 (2) मई-जून, पेज-89-93।
- https://www.uttamhindu.com
- https://www.aajkijandhara
- https://www.briefingpedia.org
- https://www.hindi.rajras.in
- https://www.reflections.live
- https://www.bachpanexpress.com
- https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf
- https://www.drishtiias.com/hindi/daily-news-analysis/national-education-policy-2020
- https://pmmodiyojanaye.in/national-education-policy-2020/
- https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A4%88_%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE_%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF_2020
- https://hindi.nvshq.org/new-national-education-policy/